PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

जवर्ष : 02
अंक : 022
दि. 22.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी की 4 घंटे की 'सुपर मीटिंग' : मिडिल ईस्ट संकट से 2047 प्लान तक, मंत्रियों को मिले टास्क

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई शाम केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ एक लंबी और अहम बैठक की। यह बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली और इसमें सरकार के कामकाज, आने वाले लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक शाम करीब 5 बजे 'सेवा तीर्थ' में शुरू हुई।

इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने से पहले इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को सरकार के बड़े 'मिड-टर्म रिव्यू' के तौर पर देखा जा रहा है।

बैठक बुलाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी?

सूत्रों के मुताबिक सरकार यह जानना चाहती थी कि अलग-अलग मंत्रालयों का काम जमीन पर कितना असर दिखा रहा है। पिछले महीनों में कौन से फैसले लिए गए, उनकी प्रगति क्या है और आगे किन क्षेत्रों पर तेजी से काम करने की जरूरत है, इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहा।

बैठक में नौ बड़े मंत्रालयों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। इनमें:

- कॉमर्स मंत्रालय
- पेट्रोलियम मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय

जैसे अहम विभाग शामिल थे।

मंत्रालयों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि वे अपने सुधारों को चार हिस्सों में समझाएं:

- कानून में बदलाव
- नियमों में बदलाव
- नीतियों में बदलाव
- काम करने के तरीके में बदलाव

इसके साथ यह भी बताना था कि इन फैसलों का आम लोगों पर क्या असर पड़ा।

2047 विजन पर पीएम मोदी का बड़ा फोकस

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को साफ संदेश दिया कि हर मंत्रालय को 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना होगा। सरकार का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है।

उन्होंने खासतौर पर 'ईज ऑफ लिविंग' यानी आम नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने वाले सुधारों पर जोर दिया। बड़ी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मंत्रालयों के बीच तालमेल की भी समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि योजनाएं सिर्फ

कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सीधा फायदा लोगों तक पहुंचे।

मिडिल ईस्ट संकट पर भी हुई गंभीर चर्चा

बैठक में पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार को चिंता है कि अगर यह संकट लंबा चला, तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे:

- ईंधन कीमतों पर असर कम हो
- खेती और खाद सप्लाई प्रभावित न हो
- एविएशन सेक्टर पर दबाव न बढ़े
- शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम सुचारु रहे

सरकार खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर सतर्क नजर आ रही है।

रक्षा मंत्री और नड्डा बैठक में क्यों नहीं थे?

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद नहीं थे क्योंकि वह दक्षिण कोरिया दौरे पर हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी जिनेवा में होने के कारण शामिल नहीं हो सके। हालांकि सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री की अगुवाई में पहले से ही मंत्रियों का एक अनौपचारिक समूह मिडिल ईस्ट संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है।

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की हालिया पांच देशों की विदेश यात्रा को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने मंत्रियों को बताया कि इन दौरों से भारत को किन रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है और आगे अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को कैसे मजबूत किया जाएगा।

सरकार का अगला बड़ा फोकस क्या है?

इस बैठक से साफ संकेत मिला कि मोदी सरकार अब अपने तीसरे कार्यकाल के अगले चरण की तैयारी में जुट चुकी है। सरकार एक तरफ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक संकटों का असर भारत पर कम से कम पड़े, इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सरकार की प्राथमिकता तीन बड़े क्षेत्रों पर रहेगी:

- आर्थिक स्थिरता
- वैश्विक चुनौतियों से निपटना
- आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाना

यानी यह बैठक सिर्फ मंत्रालयों की समीक्षा नहीं थी, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए सरकार का रोडमैप तय करने वाली रणनीतिक कवायद भी मानी जा रही है।

दिल्ली: राशन के लिए डिजिटल सिस्टम शुरू, बिना अंगूठा लगाए नहीं मिलेगा राशन, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

(जीएनएस)।

दिल्ली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 15 तारीख से ऑनलाइन ई-पोर्टल के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

सरकार का दावा है कि अब राशन वितरण में फर्जीवाड़ा, कटौती और गड़बड़ी की गुंजाइश काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

पूरा सिस्टम ई-बायोमेट्रिक और डिजिटल तकनीक से जोड़ा गया है, ताकि सिर्फ असली लाभार्थी को ही उसका पूरा राशन मिल सके।

अब कैसे मिलेगा राशन?

नई व्यवस्था के तहत दिल्ली की सभी फेयर प्राइस शॉप्स यानी राशन दुकानों को ई-पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों से जोड़ दिया गया है। इन

मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। यानी अब लाभार्थी को राशन लेने के लिए अंगूठे या बायोमेट्रिक पहचान से खुद को सत्यापित करना होगा। जब तक पहचान पूरी तरह मैच नहीं होगी, तब तक राशन जारी नहीं किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी व्यक्ति को तय मात्रा से कम राशन न मिले। पूरा वितरण डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा और तभी अपडेट होगा जब सही व्यक्ति को सही मात्रा में राशन मिल जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन से क्या फायदा होगा?

अब लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा रही है।

आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, उनमें शामिल हैं:

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र

परिवार के सदस्यों की जानकारी

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

आय सीमा बढ़ाने की तैयारी

दिल्ली सरकार राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

बेलूर मठ : जिनके संतों को देखते ही बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी हुए नतमस्तक

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को बेलूर मठ का दौरा किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह उनकी मठ की पहली यात्रा थी। हावड़ा में स्थित बेलूर मठ में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने संतों के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया।

हुगली नदी के किनारे स्थित बेलूर मठ जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, इसके विशाल परिसर में संतों ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का हार्दिक स्वागत किया गया। एक अधिकारी ने इसे "एक आध्यात्मिक यात्रा" बताया और पुष्टि की कि सुवेंदु अधिकारी ने पूजनीय संतों से आशीर्वाद के साथ कुछ समय व्यतीत किया।

पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद से सुवेंदु अधिकारी अपनी विशिष्ट प्रणाम शैली के लिए चर्चा में रहे हैं।

यह शैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साष्टांग प्रणाम विधि से प्रेरित मानी जाती है, और सार्वजनिक मंचों पर अक्सर देखी जाती है।

विधानसभा को किया था दंडवत प्रणाम

13 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी जब पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर, सिर झुकाकर पूर्ण दंडवत प्रणाम किया। ये तस्वीरें काफी वायरल हुईं और बंगाल की राजनीति में नई मिसाल के रूप में देखी गईं।

सीएम योगी के पैर छूकर लिया था आशीर्वाद

इससे पहले, अपने शपथ ग्रहण के दिन, सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। यह घटना तब हुई जब चुनाव प्रचार के दौरान, सीएम योगी कांथी विधानसभा में अधिकारी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे।

अब मदरसों में भी 'वंदे मातरम्' अनिवार्य! बंगाल सरकार के फैसले से फिर गरमाई राजनीति

पश्चिम बंगाल सरकार ने अब राज्य के मदरसों में भी 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के नए निर्देश के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी होगा।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में भी 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य बनाया था। अब यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसों पर लागू होगा।

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा एक्शन, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को फ्रीज कर दिया है. नवनिर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाए जाने के कारण कोर्ट ने गुरुवार को यह बड़ा फैसला सुनाया.

(जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को पूरी तरह सीज करने का एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी.

यह कड़ी कार्रवाई वार्ड संख्या-73 (फैजुल्लागंज) से नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को पिछले पांच महीनों से शपथ न दिलाए जाने के कारण की गई है. कोर्ट ने साफ कहा कि मेयर पक्ष हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से राहत पाने

में असफल रहा, इसके बावजूद अदालती आदेश, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया.

साल 2023 के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार शुक्ला विजयी घोषित हुए थे, लेकिन हलफनामे में गड़बड़ी के चलते कोर्ट ने दिसंबर 2025 में उनका निर्वाचन रद्द कर सपा समर्थित ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट से भाजपा प्रत्याशी की याचिका खारिज होने के बाद भी पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जा रही थी. मामले में सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.

अब डीएम और नगर आयुक्त संभालेंगे नगर निगम की कमान

हाईकोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है. अदालत के निर्देशानुसार, जब तक नए पार्षद ललित किशोर तिवारी को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे. इस दौरान लखनऊ नगर निगम के सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की पूरी कमान जिलाधिकारी (DM) और नगर आयुक्त संभालेंगे.

श्रावणी मेला-2026: बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार सतर्क, 30 जून तक सभी मेंटेनेंस कार्य पूरे करने के निर्देश

श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित

करने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को विद्युत भवन, पटना में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में ऊर्जा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को 30 जून 2026 तक सभी विद्युत मेंटेनेंस कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा सचिव सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अजय यादव ने की।

गाली-गलौज कमजोरों का हथियार... पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'गद्दार' संबंधी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए गुरुवार पीयूष गोयल ने कहा कि उनके बयान उनकी हताशा को दर्शाते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जनता बार-बार उन्हें नकार रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को निशाना बनाकर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के बयान और भाषण उनकी हताशा को दर्शाते हैं। जनता बार-बार उन्हें नकार रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है दूसरी तरफ नकारात्मक सोच वाले राहुल गांधी अपने बयानों और भाषणों में बार-बार अपना यही स्वभाव और चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गोयल ने कहा कि यह एक अलग बात है कि भारत की जनता उन्हें एक के बाद एक नकार रही है। उनकी हताशा और खुद से पैदा की गई भावनाएं और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वह स्पष्ट है। राहुल गांधी की ओर से राजनीतिक हमलों में "देशद्रोह" शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया।

क्या नक्सलवाद का खात्मा करना देशद्रोह है या कांग्रेस शासन में वर्षों तक नक्सलवाद को फलने-फूलने देना देशद्रोह है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जिस तरह से घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, वह देशद्रोह है। - पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

पीयूष गोयल ने कहा कि क्या वैश्विक मंच पर भारतीय ध्वज का सम्मान करना देशद्रोह माना जाता है, या विदेशों में भारतीय ध्वज का अपमान करना देशद्रोह है। क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना देशद्रोह माना जाता है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा कमजोरी को दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसे अंग्रेजी में गाली-गलौज कमजोरों का हथियार है कहा जाता है।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आपको खड़ा होना होगा और लड़ना होगा। जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके घरों में आकर मोदी और शाह के बारे में बात करें, तो आपको उन्हें बताना होगा कि उनका संगठन, मोदी और शाह गद्दार हैं।

उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली खुशखबरी, महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश

एएलखनऊ। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सुधि ली है।

राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा जून में मिलने वाली सैलरी और पेंशन में दिखाई देगा।

उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कुल डीए 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सराकर के इस फैसले से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिला है।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच कर्मचारियों की आय में राहत देने वाला माना जा रहा है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी आदेश के बाद लिया गया है।

जून की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा

सरकार की तैयारी है कि मई 2026 के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दें। मई महीने का वेतन जून की शुरूआत में कर्मचारियों के खातों में आता है, इसलिए जून में मिलने वाली सैलरी में इसका सीधा असर दिखेगा। कर्मचारियों की सैलरी पहले से अधिक होगी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीते दिनों दो प्रतिशत बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए/डीआर) देने का आदेश तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है।

सम्पादकीय

यूएई के बराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर हमला

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अल दफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में रविवार को एक ड्रोन हमला हुआ और उसके बाद आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ईरान और यूएई अब जानी दुश्मन बन चुके हैं। ड्रोन से बराकाह न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। इस अटैक को यूएई ने बिना किसी कारण के आतंकी हमला बताया। बहरहाल इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी समूह ने नहीं ली है। मगर यूएई का आरोप ईरान की तरफ ही है। यूएई का मानना है कि यह हमला ईरान ने ही ड्रोन के जरिए किया है। पिछले कई दिनों से ईरान-यूएई में तनातनी चल रही है। ईरान का मानना है कि यूएई खुलकर अमेरिका और इजरायल की मदद कर रहा है और उसकी भूमि से ही अमेरिकी हमले हो रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि वर्तमान जंग के दौरान ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मोसाद प्रमुख ने यूएई का गुप्त दौरा किया था। ड्रोन हमले से बराकाह संयंत्र के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक इलैक्ट्रिक जेनेरेटर में आग लग गई। यह आग संयंत्र की भीतरी परिधि के बाहर लगी थी। संघीय परमाणु नियामक प्राधिकरण (एफएएनआर) ने भी इस हमले की पुष्टि की कि आगे से संयंत्र की सुरक्षा या उसके जरूरी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी यूनिट सामान्य रूप से काम कर रही है। सभी जरूरी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्प आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें। बयान में ड्रोन हमले के स्त्रोत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ईरानी सूत्रों का कहना है कि हमने कोई हमला नहीं किया है तो फिर हमला किसने किया? क्या कोई तीसरी शक्ति अपना खेल तो नहीं खेल रही जो दोनों मुल्कों को लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इससे पहले भी 5 मई को यूएई ने कहा था कि उसके वुछ क्षेत्रों पर ईरान से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन ईरान की सैन्य कमान ने इस आरोप से इंकार किया था।

ईरानी अधिकारियों ने यूएई के उन आरोपों को भी खारिज किया था जिसमें ईरान पर हमला करने का दावा किया गया था। दरअसल यूएई को ईरान इसलिए अपना दुश्मन मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यूएई की धरती का इस्तेमाल करके ही अमेरिका ने उस पर अटैक किए हैं।

बहरहाल इस हमले ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे नाजुक संघर्ष विराम को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि वूटनीतिक प्रयास भी अब काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले के पीछे के लोगों पर बिना किसी उकसावे के आतंकवादी हमला करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वह अपनी देश की संप्रभुता पर किसी भी तरह के खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया की मदद से बने और 2020 से चालू बराकाह परमाणु संयंत्र अरब दुनिया का एक मात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 20 अरब डालर की लागत से बना यह संयंत्र यूएई की लगभग एक चौथाई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।

सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्त: ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने से अवैध पार्किंग हटाने तक निर्देश

सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा बैठक में अधिकारियों की टॉप टू बॉटम जवाबदेही तय करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने, अवैध डंपर, ओवरलोडिंग, डग्गामार बसों और नशे में ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि अब सड़क हादसों की रोकथाम के लिए टॉप टू बॉटम हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों और स्थानों पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चिह्नित कर वहां हादसों के कारणों की गहन समीक्षा की जाए और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर दिखना चाहिए। इसके लिए परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD) और जिला प्रशासन को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टंटबाजी, नशे में ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर सख्ती

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में स्टंटबाजी, नशे में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और अवैध वाहनों की आवाजाही को गंभीर समस्या बताते हुए इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डग्गामार बसों, अवैध डंपरों और बार-बार चालान होने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

साथ ही जिलों में तैनात आरटीओ और एआरटीओ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

अफसरों पर तय जवाबदेही

अवैध पार्किंग और अवैध स्टैंड पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनधिकृत पार्किंग और अवैध वाहन स्टैंड संचालित नहीं होने दिए जाएं। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि ऐसे स्टैंड्स को तत्काल हटवाया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बसें सिर्फ निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ी हों और परिवहन निगम यह सुनिश्चित करे कि केवल फिटनेस प्रमाणित बसें ही सड़कों पर चलें।

ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और त्वरित सुधार

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सीएम योगी ने ढहऊ अधिकारियों को राज्यभर में सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित करने और उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजबूत करने और एंबुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

स्कूल वाहनों और सार्वजनिक परिवहन पर निगरानी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिना फिटनेस प्रमाणपत्र कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर न उतरे। सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और परिवहन निगम केवल फिटनेस प्रमाणित बसों का संचालन करे।

सड़क सुरक्षा अभियान से राहत के संकेत

बैठक में यह भी बताया गया कि 'जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट' योजना के तहत पिछले चार महीनों में 566 लोगों की जान बचाई गई है। जनवरी से अप्रैल के दौरान सड़क हादसों में करीब 21% कमी दर्ज की गई, जबकि हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 22% गिरावट आई है। सरकार इसे सड़क सुरक्षा अभियानों का सकारात्मक असर मान रही है।

जनजागरूकता अभियान भी होगा तेज

सीएम योगी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और सुरक्षित ड्राइविंग नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जेब में सिर्फ 2000 रुपए? फिर भी लखनऊ के आसपास घूम सकते हैं ये खूबसूरत जगहें

(जीएनएस)।

लखनऊ के आसपास कई ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ 2000 रुपए के बजट में घूमने का मजा लिया जा सकता है। इनमें नैमिषारण्य, अयोध्या, दुधवा नेशनल पार्क, कानपुर और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जैसी जगहें शामिल हैं। यहां कम खर्च में घूमने, खाने और फोटोग्राफी का शानदार अनुभव मिलता है। घूमने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन कई बार बजट की वजह से लोग ट्रिप प्लान नहीं कर पाते। खासकर छात्रों और नौकरी करने वाले लोग अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां कम पैसों में अच्छा घूमने का अनुभव मिल सके। दिल्ली एनसीआर के पास तो कई स्थल हैं जहां आप बजट ट्रिप के लिए जा सकते हैं लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ से अगर सफर की शुरूआत करनी हो तो कम पैसों में कहां घूमने जाएं?

अगर आप भी लखनऊ में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अच्छी खबर यह है कि शहर के आसपास कई ऐसी शानदार जगहें मौजूद हैं जहां सिर्फ 2000 रुपए के अंदर आराम से ट्रिप पूरी की जा सकती है।

इन जगहों की खास बात यह है कि यहां पहुंचने का खर्च कम है और प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक शांति या एडवेंचर का भरपूर मजा मिलता है। कहीं जंगल सफारी है, तो कहीं ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ कम बजट में यादगार ट्रिप प्लान करने वालों के लिए ये जगहें बिल्कुल परफेक्ट हैं।

अगर आप भी कम खर्च में शानदार यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे लखनऊ के आसपास की कुछ ऐसी जगहों के बारे में, जहां 2000 रुपए में आराम से घूमकर आया जा सकता है।

नैमिषारण्य

उत्तर प्रदेश का सबसे पवित्र स्थल माना जाने वाला नैमिष धाम लखनऊ से करीब 90 किमी दूर है। यहां शांति और आध्यात्म का अनोखा अनुभव मिल सकता है। नैमिषारण्य धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां चक्रतीर्थ, गोमती नदी और प्राचीन मंदिर देखने लायक हैं। बस या बाइक से यहां कम खर्च में आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक दिन की ट्रिप के लिए यह जगह बेहतरीन मानी जाती है।

अयोध्या

कम बजट में शानदार धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या जाएं। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लखनऊ से ट्रेन या बस के जरिए यहां बेहद कम खर्च में पहुंचा जा सकता है। सरयू घाट की शाम की आरती और मंदिरों की खूबसूरती यात्रा को यादगार बना देती है। स्ट्रीट फूड का स्वाद भी यहां का बड़ा आकर्षण है।

दुधवा नेशनल पार्क

जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव चाहिए तो लखनऊ और आसपास वाले दुधवा नेशनल पार्क रवाना हो जाएं। नेचर और वाइल्डलाइफ को पसंद करने वालों के लिए दुधवा नेशनल पार्क शानदार विकल्प हो सकता है। यहां हिरण, हाथी और कई दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलता है। दोस्तों के साथ रोड ट्रिप के लिए यह जगह काफी लोकप्रिय है। बजट में रहने के लिए आसपास सस्ते होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं।

बिठूर

लखनऊ से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर कानपुर में घूमने की कई जगहे हैं। लेकिन आप गंगा किनारे बसे बिठूर की यात्रा पर जा सकते हैं। कम बजट में यहां की ट्रिप यादगार बन जाएगी। बिठूर में आप गंगा घाट पर स्नान कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाले घाट घूम सकते हैं। गंगा किनारे स्थित ब्रह्मवर्त घाट पर ब्रह्म जी ने सृष्टि की रचना की थी। यहीं उन्होंने मनु और श्रद्धा को उत्पन्न किया था। इसके अलावा यहां ध्रुव टीला है, जहां बालकाल्य में ध्रुव ने 99 साल तक तप किया था, ताकि ईश्वर की गोद में बैठ सकें। लवकुश की जन्मस्थली और ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी बिठूर में ही है। 2000 रुपये से कम में यहां की यात्रा आसानी से पूरी की जा सकती है।

नवाबगंज बर्ड सेंचुरी

नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित उन्नाव जिले में है। लखनऊ से 43 किमी का सफर तय करके यहां पहुंचा जा सकता है। यह स्थान 250 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का घर है। यह बर्ड सेंचुरी प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट जगह है।

अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति चाहते हैं, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जा सकते हैं। यहां हरियाली, झील और अलग-अलग पक्षियों की खूबसूरती देखने को मिलती है। फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए यह लो-बजट डेस्टिनेशन काफी शानदार माना जाता है।

गुंटूर से आए स्कूली छात्रों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति ने सरकारी स्कूलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का आ'ान किया

उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा- 'ईमानदारी से कड़ी मेहनत करो, सफलता में विनम्र रहो'

(जीएनएस)।

आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के स्कूली छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी राधाकृष्णन से मुलाकात की।

सरकारी स्कूलों के 27 लड़कियों सहित 41 मेधावी छात्रों के इस समूह ने कक्षा 10 की परीक्षाओं में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था और वर्तमान में वे दिल्ली के शैक्षिक दौरे पर हैं।

सरकारी स्कूल के गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को शैक्षिक दौरे पर दिल्ली लाने की पहल की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे दौरे छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने और उनके ज्ञान का विस्तार करने में मदद करते हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत करके खुशी व्यक्त की।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि सभी सफल लोगों को जीवन में संघर्ष, असफलता और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां किसी व्यक्ति को अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और सफलता के प्रति अधिक दृढ़ संकल्पित बनाती हैं। छात्रों को अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से निराश न होने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा

कि शिक्षा उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगी।

उपराष्ट्रपति ने छात्रों को याद दिलाया कि देश के कई महान वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षक, नवप्रवर्तक, उद्यमी और राजनीतिज्ञ सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों से ही निकले हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने भी एक सरकारी स्कूल में तमिल माध्यम में पढ़ाई की थी और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा जीवन को बदलने, परिवारों को ऊपर उठाने, समुदायों को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने का सबसे शक्तिशाली साधन है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी स्कूलों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों और विधायकों से सरकारी स्कूलों के सुधार और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

पिछले एक दशक में देश की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के सपने की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में छात्रों के सपने और आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि 41 मेधावी छात्रों में से 27 लड़कियां थीं। उन्होंने कहा कि यह देश में नारी सशक्तिकरण को दशार्ता है।

उपराष्ट्रपति ने छात्रों को मादक पदार्थों और हानिकारक व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी, जिनमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी शामिल है। उन्होंने छात्रों से खेलकूद, पठन-पाठन और रचनात्मकता को प्राथमिकता देने तथा अपनी पढ़ाई, लक्ष्यों और परिवार एवं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। अपने संबोधन के समापन में, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को तीन सिद्धांतों को हमेशा याद रखने की सलाह दीः ईमानदारी से कड़ी मेहनत करना, सफलता में विनम्र रहना और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना। उन्होंने सभी छात्रों को उज्ज्वल, सार्थक और सफल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्र शेखर और पश्चिम गुंटूर विधानसभा की सांसद श्रीमती गल्ला माधवी उपस्थित थीं।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस (जीएएडी) 2026 के अवसर पर दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। डीएफएस ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिव्यांगजनों द्वारा भौतिक माध्यमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिजीटल माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

डीएफएस इस बात पर जोर देता है कि सुलभता केवल एक अनुपालन आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग्राहक अनुभव, डिजिटल समावेशन और समान वित्तीय भागीदारी का एक अनिवार्य घटक है। नीतिगत समर्थन और इस विषय पर समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से, वित्तीय संस्थानों को सुलभता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सेवा वितरण और डिजिटल परिवर्तन के हर चरण में सुलभता को एकीकृत किया जा सके। इस अवसर पर डीएफएस सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और हितधारकों से एक निर्बाध और समावेशी वित्तीय परितंत्र के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की अपील करता है, ताकि कोई भी ग्राहक पीछे न छूट जाए।

केरल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी जोरों पर, महिलाओं के लिए समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम

कोट्टायम में योग और आयुर्वेद के माध्यम से रजोनिवृत्ति के दौरान स्वास्थ्य लाभ पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 की 32 दिवसीय तैयारी के हिस्से के रूप में, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से यंग विमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) कलाथिपाडी द्वारा "रजोनिवृत्ति के लिए योग - एक समग्र कल्याण मॉड्यूल" पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग और आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में समुदाय के सदस्यों, योग अभ्यासकर्ताओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस कार्यक्रम में रजोनिवृत्ति के दौरान स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों, शास्त्रीय योगिक अभ्यासों, प्राणायाम, विश्राम तकनीकों और ध्यान-आधारित उपायों को एकीकृत करने पर विषयगत सत्र शामिल थे।

इस सत्र में रजोनिवृत्ति को एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में उजागर किया गया, जिसमें हार्मोनल, भावनात्मक और चयापचय संबंधी परिवर्तन शामिल होते हैं। सत्र में यह बताया गया कि योग शारीरिक आराम, भावनात्मक संतुलन, तनाव कम करने, बेहतर नींद और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है।

प्रतिभागियों को ताड़ासन, बद्ध कोणासन, बालासन, सेतु बंधासन, विपरीत करणी और शवासन सहित सौम्य योग की परंपराओं के साथ-साथ नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसी प्राणायाम तकनीकों से परिचित कराया गया, जो तंत्रिका तंत्र के संतुलन और मानसिक कल्याण में सहायता के लिए जाने जाते हैं।

इस कार्यक्रम में वात असंतुलन और धातु क्षय पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य के लिए सहायक आहार और जीवनशैली पर जोर दिया गया।

डॉ. मलयिल साबू कोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भारत की वाईडब्ल्यूसीए, सीएमएस कॉलेज और कोट्टायम नगर प्रशासन के अन्य विशिष्ट अतिथि और वक्ता भी उपस्थित थे।

इस आयोजन ने महिलाओं के स्वास्थ्य में एक निवारक, प्रोत्साहक और चिकित्सीय माध्यम के रूप में योग की भूमिका को सुदृढ़ किया, जो पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सामुदायिक स्वास्थ्य और जीवनशैली में एकीकृत करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने मिशन लाइफ अभियान के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ चिड़ियाघर के शिक्षा केंद्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम (एसवीपी) 2026 का सफल शुभारंभ किया।

मिशन लाइफ के जन-जागरूकता अभियान के तहत आयोजित यह कार्यक्रम 'प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।' विषय पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस थीम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य युवा छात्रों में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छता और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए इंटरैक्टिव शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से कुल 854 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इनमें से 60 प्रतिभागियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के

आधार पर किया गया और पुष्टि के लिए उनसे फोन पर संपर्क किया गया। उद्घाटन दिवस पर दिल्ली-एनसीआर के 15 स्कूलों के 39 छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के पहले दिन प्रतिभागियों को एसवीपी 2026 के उद्देश्यों और गतिविधियों से परिचित कराने के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के बाड़ों का भ्रमण कराया गया।

साथ ही अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ. फैयाज ए. द्वारा जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान भी दिया गया।

यह दो सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम दो स्लॉट - स्लॉट ए और स्लॉट बी - में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्लॉट में 50 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 25 जूनियर और 25 सीनियर छात्र हैं।

कार्यक्रम की रूपरेखा में शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि वन्यजीव फोटोग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेरिटेज वॉक (धरोहर यात्रा), स्लोगन लेखन, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, स्वच्छता जागरूकता अभियान, क्ले मॉडलिंग (मिट्टी के मॉडल बनाना), निबंध लेखन, प्रदर्शनियां, विशेषज्ञ वार्ता और मिशन लाइफ जागरूकता सत्र।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम मोदी के विजन में बना स्पोर्ट्स का शानदार ईको सिस्टम, गोरखपुर में बोले सीएम योगी

(जीएनएस)।

गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से प्रदेश में स्पोर्ट्स का शानदार इकोसिस्टम विकसित हुआ है, रामगढ़ताल अब वाटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मई को 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश और उत्तर प्रदेश में पिछले 11-12 वर्षों में खेल का बेहतरीन इकोसिस्टम विकसित हुआ है। सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर कदम तत्परता से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विकसित हुए बेहतरीन इकोसिस्टम का परिणाम रामगढ़ताल है। 2017 के पहले यह गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज यहां रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ एशियाड प्रशिक्षण शिविर भी संभव हुए हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने को प्रेरित किया। खिलाड़ी हमेशा सकारात्मक सोच और टीम भावना से कार्य करता है। सीएम योगी ने 'चरैवेति-चरैवेति' को जीवन का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का अभाव था। अब हर गांव में खेल के मैदान, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्टेडियम विकसित हो रहे हैं। खेलो

इंडिया खेलो जैसे कार्यक्रमों से खेल गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। वाराणसी और गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

रामगढ़ताल वाटर स्पोर्ट्स की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में नई पहचान बना चुका है। भारत आज विश्व मानचित्र पर एक मजबूत रोइंग शक्ति के रूप में उभरा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला टीम के प्रशिक्षण हेतु रामगढ़ताल को चुना गया है। प्रशासन को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों पर वाटर स्पोर्ट्स की समृद्ध संभावना है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

खिलाड़ियों का प्रोत्साहन

सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति विकसित की है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को नौकरी की गारंटी दी गई।

ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ आदि में पदक विजेता 534 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की गई है। ये नियुक्तियां पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों में हुई हैं। 500 और खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिए नौकरी देने का कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी।

गोरखपुर के रामगढ़ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना। बालक वर्ग की चैंपियनशिप पर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की टीम ने आधिपत्य जमाया।

मुख्यमंत्री ने इन टीमों और पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सीएम योगी के नेतृत्व में खेल प्रोत्साहन की सराहना की। सांसद रविकिशन शुक्ल ने गोरखपुर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास पर जोर दिया।

बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ सहित इन जिलों में खतरनाक लू का अलर्ट

(जीएनएस)।

यूपी में 21 मई को गर्मी का प्रकोप चरम पर रहने वाला है. मौसम विभाग ने बांदा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बेहद तेज लू और गर्म रातों की चेतावनी जारी की है. दिन में झुलसाने वाली हवाएं और रात में भी बढ़ा तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. फिलहाल 23-24 मई के बाद कुछ इलाकों में हल्के बदलाव और आंशिक राहत के संकेत मिल रहे हैं.

यूपी में मई की गर्मी अब जानलेवा होने लगी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा चेतावनी के अनुसार 21 मई को प्रदेश के कई जिलों में बेहद तेज और खतरनाक लू चलने की संभावना है. हालात ऐसे बन सकते हैं कि दिन में सड़क पर निकलना मुश्किल होगा और रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलेगी. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले घंटे लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

बुंदेलखंड और मध्य यूपी में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिजार्पुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में बहुत तेज लू चल सकती है. इन जिलों में दोपहर के समय हालात सबसे ज्यादा कठिन रहने की आशंका है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि दोपहर तक गर्म हवाएं सीधे चेहरे पर आग जैसे थपेड़ों का एहसास कराएंगी. मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है.

पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी भी चपेट में

प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, फरुर्खाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और कासगंज में भी बेहद गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन जिलों में भी लोगों को दिनभर झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. पश्चिमी यूपी के शहरों में गर्म हवा और धूलभरी तपिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. वहीं पूर्वांचल के जिलों में उमस और गर्मी मिलकर हालात को और मुश्किल बना सकते हैं.

इन जिलों में भी चलेगी तेज लू

गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भी तेज गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. खुले मैदानों और सड़कों पर गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा.

रात में भी नहीं मिलेगी राहत

इस बार सबसे बड़ी चिंता सिर्फ दिन की गर्मी नहीं, बल्कि गर्म रातें भी हैं. मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में रात के समय भी ज्यादा गर्मी रहने की चेतावनी दी है. आमतौर पर रात में तापमान गिरने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस बार रात में भी गर्म हवाएं और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. बिना कूलर और एसी वाले घरों में हालात ज्यादा कठिन हो सकते हैं.

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर ढककर बाहर निकलने को कहा गया है.

शहरों में दोपहर का सन्नाटा

भीषण गर्मी का असर अब शहरों की रफ्तार पर भी दिखने लगा है. दोपहर होते-होते बाजारों में भीड़ कम होने लगती है और सड़कें सूनी दिखाई देने लगती हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. कई इलाकों में सुबह 10 बजे के बाद ही धूप चुभने लगती है. वहीं दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह तेज गर्मी और लू का असर बना रह सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की जरूरत है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है.

भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं; इनमें सहयोग और विश्वास है: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

वैश्विक संकटों के बीच भी भारत समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देने में सक्षम: श्री गोयल

निर्यात प्रोत्साहन मिशन से लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक उचित प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी: श्री गोयल

हम देश भर में उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं; हमने एक समग्र विकास मॉडल तैयार किया है: श्री गोयल

भारत अगले कम से कम 25 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: श्री गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी नवाचार, उच्च परिशुद्धता रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से सुदृढ़ होती है।

श्री गोयल ने कहा कि पिछले छह महीनों में अमेरिकी उद्योग से अनुमानित 60 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें अमेजन और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा किए गए प्रमुख डेटा सेंटर निवेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय स्तर पर परिमाण, प्रतिभा और बाजार के अवसरों का संयोजन प्रस्तुत करता है।

श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है और भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुशल प्रतिभाओं का विशाल भंडार है और 1.4 बिलियन महत्वाकांक्षी भारतीयों, बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग की मांग के कारण अमेरिकी नवाचार को व्यापक अवसर मिलते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा न्यूनतम है, जिससे साझेदारी और मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि जब पूरकता आपसी विश्वास के साथ जुड़ जाती है, तो यह एक अजेय संयोजन का निर्माण करती है जो भविष्य के लिए विश्वसनीय और गतिशील आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में सक्षम है।

श्री गोयल ने कहा कि सरकार भव्य स्कीम के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपना रही है, जिसका उद्देश्य देशभर में 100 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल औद्योगिक बुनियादी ढांचे को श्रमिक आवास, मनोरंजन और सामाजिक सुविधाओं के साथ एकीकृत करता है ताकि एक समग्र औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो सके।

श्री गोयल ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, कम लॉजिस्टिक्स लागत और मुक्त व्यापार समझौते मिलकर निवेश, विनिर्माण वृद्धि और निर्यात प्रतिस्पर्धा का एक सकारात्मक चक्र बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अगले कम से कम 25 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को शामिल करते हुए समन्वित प्रयास शुरू किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निर्यात प्रोत्साहन मिशन से लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि निर्यात निरीक्षण परिषद, भारतीय मानक ब्यूरो और एफएसएसएआई जैसी एजेंसियां भारत भर में विश्व स्तरीय परीक्षण और गुणवत्ता अवसंरचना के निर्माण के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की गतिशीलता को रेखांकित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की क्षमता, निर्णायक नेतृत्व और एक विश्वसनीय एवं पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विश्व के साथ जुड़ने के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।

श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक नेता भारत को प्रशंसा और उम्मीदों की निगाहों से देखते हैं और यह सराहना भारतीयों को एक मजबूत राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी की एक निर्णायक साझेदारी बताया, जो अमेरिकी नवाचार और निवेश के साथ-साथ भारतीय कौशल और प्रतिभा के मेल से संचालित है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर उत्पाद खरीदने और घरेलू स्तर पर असेंबल करने की पुरानी पद्धति से हटकर डिजाइन, नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में अरबों डॉलर की लागत से विकसित किए जाने वाले नवाचार भारत में एक तिहाई या एक पांचवें हिस्से की लागत से संभव हैं।

श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक कंपनियां प्रतिभाओं को विदेशों में स्थानांतरित करने के बजाय वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के लिए भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में तेजी से पहचान रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद यह बदलाव और भी तेज हो गया है, क्योंकि महामारी ने भारत जैसे विश्वसनीय साझेदारों को दूरस्थ कार्य और ऑफशोरिंग की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है।

सीएम योगी के नमाज बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कही बड़ी बात, मस्जिदों और ईदगाहों में ही होगी नमाज

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने संबंधी हालिया टिप्पणी के बाद शुरू हुई बहस के बीच कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि ईद-उल-अजहा की नमाज पहले की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अलग-अलग पालियों में नमाज की व्यवस्था भी की जा सकती है।

योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि नमाज पढ़ना आवश्यक है तो इसे मस्जिदों के भीतर अदा किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि भीड़ अधिक हो तो अलग-अलग 'पालियों' में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर नमाज पढ़ना जरूरी है तो अलग-अलग पालियों में पढ़िए। हम आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़कों पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुसलमान वर्षों से मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं- खालिद रशीद फरंगी महली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 28 मई को होने वाली ईद-उल-अजहा के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग इमामों के नेतृत्व में अलग-अलग समय पर नमाज अदा कराने की व्यवस्था की जा सकती है। मुसलमान वर्षों से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करते आ रहे हैं और हमेशा कानून-व्यवस्था का पालन करते रहे हैं, क्योंकि नमाज केवल इबादत ही नहीं, बल्कि अनुशासन भी सिखाती है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से सड़कों पर नमाज से परहेज कर मुसलमानों ने यह साबित किया है कि वे एक अनुशासित और सभ्य समुदाय हैं। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सभी समुदायों पर समान नियम लागू करेगी। आदर्श स्थिति यही होगी कि कोई भी समुदाय सड़कों पर जुलूस या धार्मिक आयोजन न करे।

नियम सभी पर समान रूप से लागू हो- यासूब अब्बास

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस वर्ष भी शिया मस्जिदों में ईद की नमाज की तैयारियां हर साल की तरह की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिया परंपरा में सामूहिक नमाज अलग-अलग 'पालियों' में अदा करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नमाज पालियों में नहीं होती। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर अब्बास ने कहा कि यह इबादत का मामला है और केवल एक प्रकार की इबादत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। कोई भी जुलूस या धार्मिक गतिविधि जो यातायात बाधित करे, उसे रोका जाना चाहिए।

बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं ने किया समर्थन

इस बीच, बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नमाज केवल साफ-सुथरे और शांत स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए, जहां किसी प्रकार की बाधा न हो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में नमाज के दौरान इबादत करने वाले और अल्लाह के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की शांति और एकाग्रता सड़कों या चौराहों पर संभव नहीं है, बल्कि मस्जिदों या घरों में ही हासिल की जा सकती है।

सीएम योगी ने कुछ गलत नहीं कहा- मौलाना खुर्शीद

बरेली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सड़कों पर नमाज का विरोध कर कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का पहले भी पालन किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा।

बहुसंख्यक समुदाय को 'खुश' के लिए दिया बयान- सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी

अमरोहा स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद के प्राचार्य मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने कहा कि इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना उचित नहीं माना जाता। बिना आवश्यक अनुमति के कहीं भी नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए और मुसलमान इस बात से अवगत हैं व अधिकांश लोग इसका पालन भी करते हैं। हालांकि, मंसूरपुरी ने यह भी कहा कि मुसलमान नमाज को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नमाज संबंधी टिप्पणी "निराधार" है और बहुसंख्यक समुदाय को 'खुश' करने के उद्देश्य से की गई राजनीतिक टिप्पणी है।

26 मई तक सामूहिक छुट्टी पर रहेंगे लखनऊ के वकील, पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लिया फैसला

17 मई 2026 की पुलिस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने 21 से 26 मई तक सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, दर्ज मुकदमे वापस लेने और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ी कई मांगें उठाई हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 मई 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने बड़ा फैसला लेते हुए 26 मई तक सामूहिक छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं के हितों और सम्मान की रक्षा को लेकर बुधवार, 20 मई 2026 को सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की संयुक्त आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में वकील शामिल हुए। सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

26 मई तक रहेगा सामूहिक अवकाश

बैठक में अधिवक्ताओं के विचार सुनने और विस्तृत चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सभा में तय किया गया कि 17 मई की घटना के विरोध में लखनऊ जनपद के सभी अधिवक्ता 21 मई 2026 से 26 मई 2026 तक पूर्ण रूप से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। सभा में वकीलों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

वकीलों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग

अधिवक्ताओं ने वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठे मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की। इसके लिए शासन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा गया है। संयुक्त आम सभा में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि सिविल कोर्ट स्थित पुरानी तहसील परिसर की भूमि सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ को लीज पर दी जाए। इसके अलावा पुराने हाई कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के खाली पड़े आवास की भूमि अधिवक्ताओं के चैंबर और पार्किंग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की मांग की गई।

पैरवी के लिए अध्यक्ष और महामंत्री अधिकृत

हाई कोर्ट में लंबित याचिका की 25 मई 2026 को होने वाली सुनवाई के लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल एडवोकेट और महामंत्री अवनीश दीक्षित एडवोकेट को अधिकृत किया गया है। दोनों नेता अधिवक्ताओं की ओर से अदालत में पक्ष रखेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि आंदोलन की अगली रणनीति प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के साथ चर्चा के बाद तय की जाएगी। इसके लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ ने 26 मई 2026 को दोपहर 2 बजे फिर आम सभा बुलाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली-एनसीआर की तरह चमकेगा लखनऊ-एससीआर, 2047 तक बनेंगे 10 नए कॉरिडोर, 6 जिलों में कनेक्टिविटी सुधरेगी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के जिलों में रहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली-ठउफ की तर्ज पर अब यूपी में भी स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे इलाके के विकास के लिए 29 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अगुवाई में हुई एक मीटिंग में इस मेगा प्लान पर मुहर लगी। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ और उसके आस-पास के इलाकों को जोड़ने के लिए 150 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

इन जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा हब

सरकार लखनऊ के साथ उसके 5 पड़ोसी जिलों को जोड़कर एक बड़ा बिजनेस और ट्रांसपोर्ट हब बनाने जा रही है। इस नए रीजन में ये 6 जिले शामिल होंगे- लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई।

इन सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए 'राज्य राजधानी माला' नाम से शानदार सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे इन शहरों के बीच आना-जाना बहुत जल्दी और आसान हो जाएगा।

गांवों तक पहुंचेंगी सुविधाएं, थमेगा बड़े शहरों की ओर पलायन

इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गांवों तक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं और तेज कनेक्टिविटी पहुंचेगी, तो लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार और बिजनेस के नए मौके मिलेंगे। इससे युवाओं का बड़े शहरों की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक रुक सकेगा।

नए उद्योगों और बिजनेस से आएगा बड़ा निवेश

इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ सड़कें और मेट्रो ही नहीं, बल्कि नए उद्योग भी लगाए जाएंगे। इसके तहत बड़े-बड़े लॉजिस्टिक पार्क और फूड पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के किनारे विशेष इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ताकि देश-विदेश की बड़ी कंपनियां यहां आकर निवेश कर सकें।

जानिए कहां-कहां से गुजरेगी नई मेट्रो

आने वाले समय में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए लखनऊ में 10 नए मेट्रो रूट (कॉरिडोर) बनाने को मंजूरी दे दी गई है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन को इसकी पूरी डिटेल में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरा काम 'विकसित भारत 2047' के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

इस योजना में शहर के सभी प्रमुख इलाकों जैसे एयरपोर्ट, आईआईएम (IIM), चारबाग और इंदिरा नगर को तो जोड़ा ही जाएगा लेकिन इसके साथ ही जानकीपुरम, मोहनलालगंज, बंथरा और बाराबंकी रोड जैसे नए इलाकों तक भी मेट्रो पहुंचेगी।

कहां और कितनी लंबी बनेगी नई मेट्रो लाइन

कल्ली पश्चिम से आईएमः यह सबसे लंबा रूट होगा, जिसकी लंबाई करीब 45 किलोमीटर होगी। सीजी सिटी से सीसीएस एयरपोर्टः इस रूट की लंबाई 19.8 किलोमीटर होगी। राजाजीपुरम से आईएमः यहां 18.42 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। चारबाग से कल्ली पश्चिमः इस रूट पर 13 किलोमीटर लंबी मेट्रो चलेगी। सीसीएस एयरपोर्ट से बंथराः यहां 11 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा। इंदिरा नगर से अनोरा कलाः इस रूट की लंबाई 9.27 किलोमीटर होगी। इंदिरा नगर से सीजी सिटीः यहां 7.7 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। मुंशीपुलिया से जानकीपुरमः इस इलाके के लोगों के लिए 6.29 किलोमीटर का रूट बनेगा। कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंजः यहां 06 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन प्रस्तावित है।

ये सभी रूट साल 2047 तक अलग-अलग फेज में बजट और प्लानिंग के हिसाब से तैयार किए जाएंगे, जिससे लखनऊ और आस-पास का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत और आसान हो सकें।

प्रदेश में प्रचंड गर्मी को देखते हुए अलर्ट पर सरकार, सीएम योगी ने दिए बिजली- अस्पताल को लेकर ये निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के दृष्टिगत अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें तथा किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

सीएम ने अधिकारियों को अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी में अधिक परेशानी बिजली कटौती और पानी की कमी से होती है। सभी डीएम अपने जिलों में नियमित समीक्षा करें और समस्याओं का

तत्काल समाधान कराएं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के इंतजाम रहें। आवश्यक दवाएं, बेड, आईवी फ्लूइड और डॉक्टरों की उपलब्धता हो। एंबुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखा जाए। बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। दोपहर में बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न जाने दें। बुजुर्गों को भी तेज धूप से बचाने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। ढीले सूती कपड़े पहनें जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। अधिक से अधिक पानी ओआरएस और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें तथा धूप में निकलते समय सिर को ढकें।

आग से बचाव का रहे इंतजाम

सीएम ने कहा कि गर्मी में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। खेतों, बाजारों, गोदामों और रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। ऐसी कोई भी लापरवाही न हो, जिससे आग लगने का अंदेशा हो। फायर विभाग पूरी तैयारी रखे। निर्माण कार्यों और खुले स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को लू, थकावट और निर्जलीकरण से बचाने के कदम उठाएं। कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। श्रमिकों से लगातार काम न कराया जाए। सभी विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखें। आमजन को गर्मी व लू से बचाव के उपायों के बारे में बताएं।

यूपी: 44 जिलों में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा, लखनऊ के केंद्र में उड़ी पेपर लीक की अफवाह; 82.29 % हुए शामिल

(जीएनएस)।

लखनऊ , यूपी के 44 जिलों में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के दौरान 861 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 861 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 34378 कक्ष निरीक्षण तैनात थे।

प्रदेश में 7994 पदों पर लेखपाल भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में पंजीकृत 366712 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 301756 कुल 82.29 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व शासन स्तर से कड़ी निगरानी की गई।

परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में आयोजित की गई थी। इसमें परीक्षा शुरू होने पर

राजधानी के गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इंटर कॉलेज, ऐशबाग के एक कमरे से पेपर लीक होने की अफवाह उड़ी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसका सत्यापन जिला प्रशासन व अन्य अधिकारियों से किया गया। इसमें यह सूचना गलत पाई गई।

आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया के अनुसार वहां पर ओएमआर व पेपर सील पैकेट में सुरक्षित थे। कमरा संख्या 21 के कुछ अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के पहले भ्रम में उठकर कमरे से बाहर आ गए थे, जिन्हें वहां उपस्थिति अधिकारियों ने सही जानकारी देते हुए परीक्षा में वापस शामिल कराया। उन्होंने बताया कि बुलंदशहर के शिवकुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज, जहांगीराबाद केंद्र पर एक संदिग्ध अभ्यर्थी मिला।

बायोमीट्रिक व अन्य डाटा से मिलान कर उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए स्थानीय पुलिस को दे दिया गया। आयोग की ओर से शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों, जिला मुख्यालयों और आयोग मुख्यालय पर बने कंट्रोल कमांड रूम से सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई। बायोमीट्रिक वेरीफिकेशन और एआई का प्रयोग कर किसी दूसरे के परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों को रोका गया। परीक्षा के दौरान 861 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 861 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 34378 कक्ष निरीक्षण तैनात थे।

समय पर स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान और देखभाल तक समान पहुंच, मजबूत और जन-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों का आधार हैं: श्री नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान "फेफड़ों की जांच पर मंत्रिस्तरीय दृष्टिकोण" विषय पर आयोजित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कार्यक्रम को संबोधित किया

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और 'टीबी-मुक्त भारत' की परिकल्पना के तहत, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शीघ्र निदान प्रयासों में से एक को अंजाम दिया है।'

'आणविक परीक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल चेस्ट एक्स-रे सेवाएं, एआई-सहायता प्राप्त उपकरण, हैंडहेल्ड स्क्रीनिंग उपकरण और विकेन्द्रीकृत परीक्षण प्रणालियों को देश के दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में निदान में देरी को कम करने के लिए व्यापक रूप से तैनात किया जा रहा है'

'टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से, भारत ने टीबी रोगियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए नागरिकों, संस्थानों, निगमों और समुदायों को एकजुट किया है'

भारत का टीबी मुक्त भारत ऐप, जिसमें एआई-सक्षम बहुभाषी चैटबॉट "खुशी" शामिल है, उपयोगकताओं को लक्षणों, अधिकारों और निकटतम निदान सुविधाओं के बारे में रियल-टाइम जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्तर पर फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग के लिए व्यावहारिक और समग्र समाधान विकसित करने में सरकारों, नवोन्मेषकों, भागीदारों और समुदायों के साथ सहयोग की तत्परता को दोहराया

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान "फेफड़ों की जांच पर मंत्रिस्तरीय दृष्टिकोण" विषय पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। "क्या आपकी स्वास्थ्य प्रणाली फेफड़ों की जांच में चुनौतियों का सामना कर रही है?" विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने किया था, जिसमें भारत, जापान, फिलीपींस और जाम्बिया ने सह-आयोजक के रूप में भाग लिया।

श्री नड्डा ने उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर जांच, शीघ्र निदान और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच, सुदृढ़ और जन-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों का आधार हैं। उन्होंने कहा

कि फेफड़ों की स्वास्थ्य जांच को मजबूत करना केवल प्रौद्योगिकी या निदान उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन बचाने, पीड़ा कम करने, स्वास्थ्य संबंधी भारी खर्चों को रोकने, आजीविका की रक्षा करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने से संबंधित है।

भारत की टीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और 'टीबी-मुक्त भारत' की परिकल्पना के अंतर्गत, भारत ने विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान प्रयासों में से एक को अंजाम दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश ने घर-घर जाकर जागरूकता अभियान, मोबाइल स्क्रीनिंग टीमों, सामुदायिक अभियानों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील आबादी के बीच लक्षित अभियानों के माध्यम से संवेदनशील आबादी में सक्रिय मामलों की पहचान का विस्तार किया है।

श्री नड्डा ने आगे बताया कि भारत ने टीबी और फेफड़ों की अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए आधुनिक निदान प्रणालियों को काफी हद तक विकसित किया है। निदान में देरी को कम करने के लिए, विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में, आणविक परीक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल चेस्ट एक्स-रे सेवाएं, एआई-सहायता प्राप्त उपकरण, हैंडहेल्ड स्क्रीनिंग डिवाइस और विकेंद्रीकृत परीक्षण प्रणालियों को व्यापक रूप से तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवाचार समानता के लिए होना चाहिए और प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुधारों और अग्रिम पंक्ति के कार्यबल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं समुदायों के करीब पहुंच सकी हैं। उन्होंने कहा कि केवल बीमारी का निदान करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पोषण संबंधी सहयोग, उपचार का पालन सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और सामुदायिक एकजुटता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से, भारत ने टीबी रोगियों और उनके परिवारों की मदद के लिए नागरिकों, संस्थानों, निगमों और समुदायों को एकजुट किया है।

भारत की डिजिटल पहलों के बारे में चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने बताया कि मंत्रालय ने टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है जिसमें "खुशी" नामक एक एआई-सक्षम बहुभाषी चैटबॉट शामिल है, जिसे शुरूआती स्तर के स्मार्टफोन पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म लक्षणों, अधिकारों और निकटतम निदान सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शन करता है, जिससे लक्षणों की शुरूआत और समय पर उपचार के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलती है।

श्री नड्डा ने मजबूत वैश्विक सहयोग का आ'ान करते हुए फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रस्ताव रखा। इनमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ढांचे के अंतर्गत फेफड़ों के स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाना, निदान, डिजिटल उपकरणों और स्क्रीनिंग तकनीकों तक किफायती पहुंच का विस्तार करना, श्वसन स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना, नवाचार, घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और टीबी तथा फेफड़ों की अन्य बीमारियों की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के लिए सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना शामिल है।

वैश्विक लक्ष्यों से पहले टीबी को समाप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों, बेहतर निदान, स्वच्छ वातावरण, बेहतर पोषण और अधिक न्यायसंगत समाजों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि वे विलंबित निदान से शीघ्र निदान की ओर, खंडित कार्यक्रमों से एकीकृत देखभाल की ओर और रोग नियंत्रण से स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन की ओर अग्रसर हों।

अपने संबोधन के समापन में श्री नड्डा ने विश्व स्तर पर फेफड़ों की जांच के लिए व्यावहारिक और व्यापक समाधानों को आगे बढ़ाने में सरकारों, नवप्रवर्तकों, विकास भागीदारों और समुदायों के साथ सहयोग करने के लिए भारत की तत्परता को दोहराया।

सड़क पर नमाज आस्था नहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा

अगर बिना लाग-लपेट मुझे अपनी बात कहनी हो तो पहले मैं पूछूंगा- क्यों, मुख्यमंत्री के तार्किक बयान का आखिर विरोध क्यों? क्या इस देश में नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी और कौन सा कानून यह अधिकार देता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए? मैंने लंबे समय तक पुलिस अधिकारी का दायित्व निभाया है और कानून व्यवस्था की हजारों स्थितियां देखी हैं। इसलिए यह कहने में मुझे रंच मात्र भी हिचक नहीं कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज का मुद्दा न तो धर्म का है, न आस्था का, यह विशुद्ध रूप से कानून-व्यवस्था, अनुशासन और राज्य की संप्रभुता का प्रश्न है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली अराजकता पर अंकुश लगाया। उन्होंने जो रुख अपनाया है, वह न केवल संवैधानिक दृष्टि से सही है, बल्कि किसी भी सभ्य और विधि-सम्मत समाज को यह रुख अपनाना ही चाहिए।

वोटबैंक की राजनीति में विरोध

तुष्टिकरण की राजनीति करनेवालों के बारे में मेरी यह धारणा रही है कि या तो वे भ्रमित हैं या फिर अपने वोटबैंक की राजनीति में न सच्चाई देखना चाहते हैं और न संविधान या कानून। ऐसे लोग मानवीय मूल्यों की भी अनदेखी करते हैं। क्या विरोध करने वालों ने कभी सोचा है कि एक एंबुलेंस जब किसी मरीज को लेकर जा रही हो और सड़क पर सैकड़ों लोग नमाज में बैठे हों, तो उस मरीज के परिजनों की क्या मनःस्थिति होगी? क्या उनकी पीड़ा कम महत्वपूर्ण है? क्या एक नागरिक, जो हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान भी हो सकता है, जो उस सड़क से गुजरना चाहता है, उसका अधिकार किसी की सामूहिक धार्मिक गतिविधि से कमतर है? यह प्रश्न असुविधाजनक हैं, लेकिन इनका उत्तर उन्हें देना होगा जो विरोध का झंडे उठाए घूम रहे हैं।

स्वीकार नहीं तुष्टिकरण की राजनीति

भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों स्पष्ट हैं। सार्वजनिक मार्ग को बाधित करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे कार्य जो आम जनता के आवागमन में बाधा डालें, कानूनी रूप से प्रतिबंधित हैं। यह कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बना, यह सबके लिए है। इसका उल्लंघन करने वालों का यदि कोई राजनीतिक दल समर्थन करता है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि इसके मूल में तुष्टिकरण ही है। किसी विशेष धर्म के लिए अलग कानून.. यह सोच ही खतरनाक है और तुष्टिकरण के ठेकेदारों का खोखलापन उजागर करती है। पूरे देश में तुष्टिकरण करने वालों को जनता ने नकारा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, बिहार में आरजेडी व महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हार में स्पष्ट संदेश निहित है कि जनता अब तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण व परिवारवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करने वाली। वह राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है।

यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल

अतिक्रमण को मिला था सरकारी संरक्षण

मैंने उत्तर प्रदेश में वर्षों तक पुलिस सेवा की है। मैंने देखा है कि किस प्रकार धीरे-धीरे सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अतिक्रमण होता है। पहले एक छोटा समूह एक कोने में नमाज पढ़ता है, फिर संख्या बढ़ती है, फिर सड़क का एक हिस्सा घिर जाता है, फिर पूरी सड़क। यह क्रमिक अतिक्रमण की प्रक्रिया है, जिसे प्रारंभ में ही न रोका जाए तो बाद में रोकना कठिन या असंभव जैसा हो जाता है। विडंबना यह कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों ने इस प्रवृत्ति को रोकने के बजाए, इसे संरक्षण देने का ही प्रयास किया। समाजवादी और कांग्रेस सरकारों में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों में इफ्तार पार्टियां होती थीं और नमाज पढ़ी जाती थी। केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों में रोजा इफ्तार करने की होड़ लगी रहती थी। इन लोगों के यहां हिंदू त्योहारों पर कोई समारोह आयोजित करने की कल्पना करना भी महा पाप था।

हनुमान गढ़ी के सामने इफ्तार का प्रयास

मैंने वह दिन भी देखा है जब सपा सरकार (स्व. मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली) में एक आईजी ने अयोध्या में हनुमान गढ़ी के ठीक सामने इफ्तार आयोजित करने का प्रयास किया और इसके लिए वहां के महंतजी को राजी भी कर लिया। लेकिन, एक कर्मठ, निष्ठावान आईपीएस अधिकारी जो वहां एसएसपी के रूप में तैनात थे, ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि यह आदेश मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मस्जिदें नहीं हैं? क्या ईदगाहें नहीं हैं?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि जगह की कमी है तो शिफ्टों में नमाज पढ़ें। इसमें गलत क्या है? यह एक व्यावहारिक और सम्मानजनक समाधान है। इसमें आपत्ति किसे है और क्यों है? मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब को तो इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता और वह खुद मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें। विरोध ऐसे लोगों को है, जो पूरे मुस्लिम समुदाय को अपने वोटबैंक के रूप में देखते हैं। जिन्हें इसके बहाने तुष्टिकरण की राजनीति को हवा देने का मौका मिलता है।

धर्म की स्वतंत्रता असीमित नहीं

संविधान का अनुच्छेद-25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह असीमित नहीं है। संविधान यह भी कहता है कि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। सड़क पर नमाज पढ़ना और यातायात बाधित करना निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वे पूरा संविधान पढ़ें, केवल वह हिस्सा नहीं जो उनके एजेंडे के अनुकूल हो। ऐसे लोगों के लिए यह मुद्दा धर्म का नहीं चुनाव का है। उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन ने इस विषय में जो सख्ती दिखाई है, वह केवल कानून-व्यवस्था की बहाली नहीं है, यह एक सांकेतिक संदेश भी है कि इस राज्य में कोई भी समूह यह नहीं मान सकता कि उसके लिए कानून अलग है।

यह संदेश आवश्यक है, क्योंकि जब कानून की धार कुंद पड़ती है, जब प्रशासन राजनीतिक दबाव में झुकता है, तो समाज में एक वर्ग मान लेता है कि वह कानून से ऊपर है। और जिस दिन यह धारणा बन जाती है, उस दिन से कानून-व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि योगी सरकार के इस निर्णय को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। कानून का राज स्थापित करना किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह सबके पक्ष में, सबके हित में होता है। विडंबना यह है कि कुछ लोग यह जानते हुए भी इसे समझना नहीं चाहते।

बिजली संकट से कारण रात में बिगड़े हालात, सड़कों पर उतरे उपभोक्ता, त्रस्त लोगों ने कई जगह लगाया जाम

(जीएनएस)।

लखनऊ, भीषण गर्मी से बिजली की मांग बढ़ चुकी है। कटियाबाज भी धड़ल्ले से बिजली जला रहे हैं। ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर और केबल फुंक रहे हैं। फॉल्ट भी आ रहा है जिसे खोजने और ठीक करने में घंटों लग रहे हैं। खासकर रात में बिजली गुल होने पर लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। बुधवार रात बिजली के लिए उपकेंद्रों पर हंगामा-घेराव, सड़क जाम की कई घटनाएं हुई।

फैजुल्लागंज में सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा

फैजुल्लागंज की द्वारिका कॉलोनी में भारत लॉन के पास बिजली नहीं आने से लोग देर रात सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। कुछ ही देर में मड़ियांव पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां फटकार उपभोक्ताओं को खदेड़ दिया। लोगों कहना है कि 10 दिन से बिजली की बेहिसाब कटौती से हम परेशान हैं।

सेक्टर-5 उपकेंद्र पर देर रात हुआ प्रदर्शन

गोमती नगर स्थित सेक्टर-5 उपकेंद्र की बदहाल विद्युत व्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं के सब्र का बांध बुधवार की रात टूट गया। यहां लगातार तीन दिन से रात करीब 10 बजे के बाद बिजली के केबल जलने की घटनाओं से लोग कटौती की मार झेल रहे थे। बुधवार देर तक बिजली गुल रहने पर उपकेंद्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वह आंदोलन करेंगे।

ओवरलोडिंग से फीडर ठप, केबल भी जले

गुडंबा। भीषण गर्मी के बीच जानकीपुरम जोन समेत आसपास के इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। ओवरलोडिंग के कारण देर रात मिश्रपुर फीडर डाउन हो गया जिससे करीब 300 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं, कई जगह एबीसी के धू-धू कर जलने से लोगों में दहशत फैल गई। नहर रोड और स्कॉर्पियो क्लब क्षेत्र में बिजली केबल में पेटी फ्यूज उड़ने के साथ आग लग गई। इससे कई इलाकों में करीब दो घंटे तक बिजली गुल रही।

फॉल्ट सही करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत

फैजुल्लागंज क्षेत्र में बिजली की फॉल्ट ठीक करने के दौरान लाइनमैन की मौत हो गई। नीलकंठ फीडर पर खराबी आई थी। लाइनमैन उदयराज शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे। संविदाकर्मी बृजेश नीचे मौजूद था। प्लास से केबल की जांच करते समय उदयराज को अचानक करंट लगा। उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पोल से नीचे सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल उदयराज को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उदयराज मूलरूप से गोंडा जनपद के निवासी थे। वर्तमान में फैजुल्लागंज की जैन कॉलोनी में रहकर नौकरी कर रहे थे। (संवाद)

कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने मोहान रोड पर लगाया जाम

देर रात एफसीआई उपकेंद्र के तहत बुद्धेश्वर से मोहान रोड पर बिजली उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पिंक सिटी कॉलोनी के उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन नहीं उठते। पता ही नहीं चल पाता कि बिजली क्यों गई है और कब तक आएगी। इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया।

उपकेंद्र पहुंचकर बनाया दबाव लेकिन नहीं मिली राहत

अंबेडकर यूनिवर्सिटी उपखंड के अंतर्गत हरिकंशगढ़ी कॉलोनी में बुधवार रात 9 बजे से देर रात तक बिजली गुल रही। कॉलोनी के लोगों ने उपकेंद्र पहुंचकर दबाव बनाया तो किसी तरह एक फेस की लाइन चालू हुई, लेकिन वोल्टेज इतना कम था कि उससे पंखा भी नहीं चल पा रहा था। पूरी रात गर्मी से कॉलोनीवासी बेहाल रहे।

तालकटोरा उपकेंद्र का का किया घेराव, धरने पर बैठे

बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने बुधवार को तालकटोरा उपकेंद्र का घेराव किया और प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। उपभोक्ताओं के समर्थन में पश्चिम क्षेत्र के सपा विधायक अरमान खान भी बैठ गए। विधायक ने कहा कि पावर हाउस पर न कर्मचारी मिलते हैं न अधिकारी। यही कारण है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। एक घंटे बाद चौक के अधिशासी अभियंता रमन वासुमित्र मौके पर पहुंचे और विधायक को मनाने का प्रयास किया। विधायक ने कहा कि इलाके के लोग बिजली कटौती और उसकी आवाजाही से परेशान हैं। कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है। 1912 पर की गई शिकायतों का बिना जांच किए ऑनलाइन निस्तारण प्रदर्शित कर दिया जाता है। विधायक ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान न होने पर अनशन किया जाएगा। (संवाद)

राजाजीपुरम अपट्रॉन उपकेंद्र पर हंगामा

लखनऊ। राजाजीपुरम अपट्रॉन उपकेंद्र के भवानीगंज इलाके में मंगलवार देर रात करीब 200 घरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। आक्रोशित उपभोक्ता उपकेंद्र पहुंच कर हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ता देख कर्मचारियों ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने समझा कर लोगों को शांत कराया। देर रात करीब 12 बजे यहां की आपूर्ति बहाल हुई। वहीं, राजाजीपुरम के एफ ब्लॉक, मल्टीस्टोरी के आसपास मंगलवार की रात बिजली की आवाजाही से परेशान रहे।

तेलीबाग के भीम टोला में 15 घंटे तक गुल रही बिजली

तेलीबाग के भीम टोला में मंगलवार के शाम 9 बजे कटी बिजली 15 घंटे बाद आई। स्थानीय निवासी अजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सुबह 4 बजे बिजली आने के बाद 5 बजे अचानक एबीसी लाइन में धमाके होने लगे। केबल टूट कर गिरने लगे। ट्रांसफार्मर के पास केबल बंच में आग लगने से फिर बिजली कट गई जो दोपहर एक बजे बहाल हो सकी। बलदेव विहार में मंगलवार रात 250 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया, जिसे बाद में बदला गया। गांधीनगर उत्तरेटिया, पाठकपुरम, सरस्वतीपुरम, सैनिक नगर में भी बिजली की आवाजाही से लोग परेशान हुए।

शॉर्ट सर्किट के बाद हाई वोल्टेज से जल गए उपकरण

पाल तिराहा न्यू उपकेंद्र के शेखपुर-हबीबपुर स्थित यूनाइटेड प्रेसिडेंट स्कूल के पास मंगलवार रात 1:45 बजे बंच कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।

जलता हुआ तार सड़क पर पड़े कूड़े पर गिरा और ट्रांसफार्मर जलने लगा। मरम्मत के दौरान इरम डिग्री कॉलेज के आसपास और अमन विहार के लगभग 800 घरों की बिजली आपूर्ति बुधवार सुबह साढ़े सात बजे तक बंद रही। स्थानीय निवासी मंजूरुल हसन और महमूद आलम ने बताया कि उनके तीन कूलर, मोबाइल चार्जर, वाईफाई के अलावा मोहल्ले में आठ से 10 घरों के उपकरण जलने से खराब हो गए।